

योगी सरकार के बजट में राजधानी लखनऊ के हाथ भी कई सौगातें आईं। खासतौर पर शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सरकार ने कई परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ाने के लिए अच्छे खासे बजट का प्रावधान किया है। कई जगह नए निर्माण के लिए रकम का प्रावधान है तो कुछ जगहों पर बजट की कमी से रुके कामों को दोबारा शुरू करने के प्रयास भी हैं। औद्योगिक क्षेत्र ने भी सरकार के बजट को सराहा है। साथ ही उम्मीद जताई कि योजनाओं के कार्यान्वयन से विकास को गति मिलेगी।

लखनऊ में आईटी और वेलनेस सिटी के लिए 600 करोड़

सौगात

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। एलडीए की दो परियोजनाओं को भी बजट मिलने का रास्ता साफ हुआ है। उसकी आईटी सिटी तथा वेलनेस सिटी योजना को भी बजट मिलेगा। दोनों योजनाओं को 300-300 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक सहमति आवास विभाग ने दी है।

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण व नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत नयी टाउनशिप विकसित करने के लिए जो 3000 करोड़ की व्यवस्था की है उसी से इस परियोजना को बजट मिलेगा।

एलडीए सुल्तानपुर रोड पर दो नयी टाउनशिप विकसित करने जा रहा है। इसमें एक आईटी सिटी व दूसरी वेलनेस सिटी योजना है। इन दोनों टाउनशिप का डीपीआर व प्रस्ताव तैयार कराकर प्राधिकरण ने शासन को भेज दिया है। एलडीए ने इन टाउनशिप के विकास के लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण व नए शहर प्रोत्साहन योजना से लिए बजट मांगा था। पिछले महीने प्राधिकरण उपाध्यक्ष की आवास विभाग के आला अफसरों के साथ बैठक हुई थी। दोनों के लिए 300-300 करोड़ के बजट की सैद्धान्तिक सहमति मिल गई थी। शासन ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण, नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत नयी टाउनशिप के विकास के लिए 3000 करोड़ है। एलडीए को इन दोनों योजनाओं को बजट मिलेगा।

1582 एकड़ में आईटी सिटी व 1300 एकड़ में वेलनेस सिटी बनेगी: एलडीए 1582 एकड़ में आईटी सिटी तथा करीब 1300 एकड़ में वेलनेस सिटी बनाने जा रहा है। इनका डीपीआर तैयार हो गया है। जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव भी शासन पहुंच चुका है। दोनों योजनाओं में जमीनों के अधिग्रहण पर लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च होगा। इनके लिए सोनी पुरवा, वीरमपुर, कुंवर बहादुर खेड़ा, सिद्धपुरा, जगमत खेड़ा, उम्मीद खेड़ा, जगन्नाथ गंज, परेहटा, रकीबाबाद, आदमपुर तथा तकिया की जमीन ली जा रही है।

६६

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण, नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत नयी टाउनशिप के लिए सरकार ने 3000 करोड़ का प्रावधान किया था। शासन ने पूर्व में एलडीए की इन दोनों योजनाओं के लिए 300-300 करोड़ देने की सैद्धांतिक सहमति दी थी। इसी से दोनों परियोजनाओं को धन मिलेगा। -डा. इन्द्रमणि त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, एलडीए

राजधानी में 225 करोड़ से विश्वस्तरीय 7 सड़कें बनेंगी

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। राजधानी की सात सड़कों को विश्वस्तरीय बनाया जाएगा। इन सड़कों पर कहीं कोई भी चीज खुले में नहीं होंगी। हरियाली से आच्छादित इन सड़कों पर न कोई तार दिखाई देगे न बेतरतीब दुकानें। बड़े ट्रांसफार्मर को हटाकर छोटे कम्पैक्ट लगाए जाएंगे। इन सात सड़कों के निर्माण पर लगभग 225 करोड़ खर्च होगा। सीएम ग्रिड योजना से इन सड़कों का निर्माण होगा। सरकार ने इसके लिए 800 करोड़ के बजट प्रावधान किया है।

मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (सीएम ग्रिड) से शहर की सड़कों को विश्व स्तरीय बनाने का प्रस्ताव किया गया है। बजट में राज्य सरकार ने सोमवार को इस स्कीम में 800 करोड़ का प्रावधान किया है। लखनऊ नगर निगम ने सीएम ग्रिड योजना से राजधानी की सात सड़कों की योजना तैयार करायी है।

६६

सीएम ग्रिड योजना से लखनऊ की सात सड़कें विश्व स्तरीय बनाई जाएंगी। इसके लिए सरकार ने बजट में 800 करोड़ का प्रावधान है। इसमें सवा दो सौ करोड़ रुपए से राजधानी की इन सात सड़कों को विश्वस्तरीय बनाया जाएगा।

-महेश वर्मा, मुख्य अभियन्ता, नगर निगम

ऐसे विश्वस्तरीय बनेंगी ये सड़कें: इन सात सड़कों पर नाले-नालियां, बिजली, टेलीफोन, ब्राण्डबैण्ड सहित अन्य सभी सेवाएं भूमिगत होंगी। नया ड्रेनेज सिस्टम बनेगा। तेज बारिश पर भी यहां पांच मिनट में पानी निकल जाएगा। दोनों तरफ फुटपाथ बनेंगे। कोई दुकानें बेतरतीब नहीं होंगी। अतिक्रमण नहीं होगा।

दिल्ली की तर्ज पर एयर सिटी के निर्माण का रास्ता हुआ साफ

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली की तर्ज पर राजधानी में भी एयर सिटी बनाने का रास्ता साफ हो गया है। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को बजट भाषण में निर्माण की घोषणा। बजट में कहा कि कहा कि लखनऊ में 1500 एकड़ में एयर सिटी विकसित की जाएगी। एयरपोर्ट के आस पास इसका निर्माण होगा।

सरोजनीनगर के अमौसी में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। दो नए टर्मिनल भी बनकर तैयार हो गये हैं। यहां से कानपुर के लिए नया एक्सप्रेस भी तेजी से बन रहा है। 104 किलोमीटर लम्बा नया आउटर रिंग रोड भी करीब है। कई डिफेंस इण्डस्ट्री भी इसके करीब हैं। आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में आवासीय, व्यावसायिक गतिविधियां और बढ़ेंगी। इसके लिए एयरपोर्ट के पास जमीन देखी जा रही है। शासन ने एलडीए को जमीन तलाशने को कहा था। एलडीए जमीन तलाश

3000

करोड़ शहरी विस्तारीकरण, नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत नई टाउनशिप के लिए

- दोनों योजनाओं को तीन-तीन सौ करोड़ की सैद्धांतिक सहमति
- सुल्तानपुर रोड पर दो नयी टाउनशिप विकसित करेगा एलडीए

300 करोड़ मिलने की उम्मीद

इस परियोजना को आवास विभाग से बजट मिलेगा। फिलहाल इसके लिए 300 करोड़ रुपए मिलने की बात कही जा रही है। आवास विभाग को जो 3000 करोड़ का बजट दिया गया है।



रहा है। अब राज्य सरकार ने इस परियोजना को बजट देने का फैसला किया है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में धन का प्रावधान भी कर दिया गया है। सोमवार को बजट भाषण में खुद वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी। सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण तथा नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत टाउनशिप विकसित करने के लिए बजट में 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।